स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं तो छात्र काहे को आएंगे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। मेज-कुर्सी, ब्लैकबोर्ड, कक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी वाले सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति बढ़ती जा रही है। हथीन में स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीमों को 46 विद्यालयों में बहुत कम छात्र मिले जबकि पंजीकरण संख्या कहीं ज्यादा थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर खंड शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की है।

सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के कारण अधिकतर परिजन अपने बच्चों को इनमें दाखिला कराने से बचते हैं। इनमें अधिकतर निम्न आय वर्ग परिवारों के बच्चे ही खिचड़ी खाने और पढ़ने जाते हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है इससे समझा जा सकता है कि इन स्कूलों के चपरासी भी अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा जनगणना, बीएलओ, मतदाता सूची अपडेशन आदि जैसे कामों में लगाया जाता है। स्कूल में रहते हैं तो पढ़ाने के साथ मिड डे मील बनवाने और बंटवाने जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें लगाया जाता है। शिक्षण स्तर अच्छा नहीं होने के कारण इन विद्यालयों में बहुत कम छात्र दाखिला लेते हैं।

घोषणावीर खट्टर ने मॉडल संस्कृति स्कूलों की घोषणा कर सुर्खियां तो बटोर लीं लेकिन इन स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षकों के पच्चीस से तीस फीसदी तक पद खाली हैं। नगला गूजरान के मॉडल संस्कृति स्कूल में तो कक्षा छह से आठ तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाला एक भी शिक्षक नहीं हैं। केवल एक संस्कृत भाषा की शिक्षिका हैं, इन पर तीन कक्षाओं के 380 विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। समझा जा सकता है कि संस्कृत की शिक्षिका बच्चों को क्या विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाएंगी और क्या बच्चे समझेंगे। कमोबेश यही हाल सभी सरकारी स्कूलों का है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में कौन अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला करवाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझ कर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही, केवल बेहतर शिक्षा देने का दिखावा कर रही है। शिक्षकों की भर्ती न कर सरकार न केवल निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है, अपना वेतन खर्च भी घटाना चाहती है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है।

शिक्षा विभाग के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार पंजीकरण मानक पूरा न होने पर ये शिक्षक फर्जी दाखिले कर लेते हैं और इनकी फीस भी अपनी जेब से भरते हैं। नौकरी बचाने की कवायद में यह फर्जीवाड़ा लगभग हर सरकारी स्कूल में किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसकी पोल भले ही खुली हो लेकिन स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर केवल औपचारिकता ही पूरी की गई है। बढ़े हुए पंजीकृत छात्रों के लिए सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का हिस्सा भी तो विभाग के इन्ही आला अधिकारियों तक पहुंचता है। ऐसे में कागज पर सब कुछ दुरुस्त रखने की कवायद की जाती है।

शिक्षा से वंचित बच्चों के सर्वे का ड्रामा

शिक्षा विभाग अब बीच में शिक्षा छोड़ने वाले और शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कर ड्रामा करेगा। पहचान के बाद ये बच्चे पढ़ाई से फिर जुड़ेंगे या नहीं इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। हां, प्रति बच्चा दो हजार रुपये मिलेगा जिसकी बंदरबांट होगी।

खबरों के अनुसार गुड़गांवां में समग्र शिक्षा गुरुग्राम की ओर से 22 से 29 नवंबर के बीच शिक्षा से वंचित और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए 93 वालंटियर्स और सरकारी स्कूलों के 363 शिक्षक लगाए जाएंगे। तलाशे गए सात साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा जबकि सात से 14 वर्ष उम्र के बच्चों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, उन्हें एजुकेशन वालंटियर्स पढ़ाएंगे। समझने वाली बात है कि इन बच्चों की तलाश आधा शिक्षण सत्र होने के बाद की जा रही है। सात साल से छोटे बच्चों का छह माह का जो कोर्स छूट गया है उसे कैसे पूरा कराया जाएगा ? पढ़ाई से दूर होने के कारण ये वैसे भी कमजोर हैं ऐसे में कोर्स पूरा करने का जोर उन्हें मानसिक दबाव में ला सकता है, शिक्षा विभाग को यह बात समझ में नहीं आती। इसी तरह सात साल से बड़े बच्चों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, यह कोर्स कोई शिक्षक नहीं कराएगा बल्कि एजुकेशन वालंटियर्स पूरा कराएंगे। प्रत्येक छात्र का शैक्षणिक स्तर अलग होने के कारण एक ही ब्रिज कोर्स सब पर लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये सर्वे और इन बच्चों को पढ़ाने की कवायद केवल ड्रामा ही साबित होने वाली है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुड़गांव में जनवरी 2023 में 2349 बच्चे शिक्षा से वंचित पाए गए थे। इनको 93 सेंटरों में ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 46.98 लाख रुपये खर्च किए हैं। केवल दस महीने में ही फिर से शिक्षा से वंचित बच्चों की खोज की जा रही है।

समझने वाली बात यह है कि न किसी न बच्चे तलाशने हैं न किसी ने पढ़ाना है, न इसकी कोई ठोस योजना है। यह केवल एक ऐसी ड्रामेबाजी है जिसके द्वारा खट्टर सरकार अपने संघी लगुए भगुओं को इस नाटक का किरदार बनाकर सरकारी पैसे का बंदरबांट कर देगी।

सरकारी कर्मचारियों को एक और मनोहर धोखा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद। अनाप-शनाप घोषणायें करने व जनता को धोखा देने में माहिर, जुमलेबाज़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली नवम्बर यानी हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में घोषणाओं का ढेर लगा दिया। यूं तो तमाम घोषणायें थोथी एवं जनता को बहकाने वाली ही होती हैं, परन्तु सरकारी कर्मचारियों को 'कैशलेश चिकित्सा सेवा' देने की घोषणा कतई सफेद झूठ साबित हो रही है।

सेवारत एवं पेंशनर्स के लिये निजी अस्पतालों में इलाज कराने के बाद बिल को अपने विभाग में जमा कराने के बाद खर्च किये गये पैसे मिलने का प्रावधान रहा है। प्रावधान तो रखा गया था लेकिन इस पैसे की वसूली करने में कर्मचारी अथवा पेंशनर द्वारा चक्कर लगाने में कई जोड़े जूते घिस जाते हैं। विभाग बिल की तस्दीक करने के लिये सिविल सर्जन को भेजता है। वहां से मंजूर होकर आने के बाद राज्य के मुख्यालय में भेजता है, वहां से वित्त विभाग को भेजा जाता है। इस सारी प्रक्रिया में वर्षों का समय तो लगता ही है, फ़ाइल को आगे सरकाने के लिये बाबुओं की जो भेंट-पूजा करनी पड़ती है वो अलग से।

बिल वसूली की इस अति कष्टदायक प्रक्रिया के विरोध में जब कर्मचारियों ने आवाज़ बुलंद की तो करीब चार साल पूर्व खट्टर जी ने 'कैशलेश चिकित्सा' की घोषणा की थी। इस प्रणाली में कर्मचारी अथवा पेंशनर सीधे उन निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं जो कि सरकारी पैनल पर पंजीकृत होते हैं। बिल का पैसा, अस्पताल वाले सीधे सरकार से ले लेंगे। इसी घोषणा को खट्टर जी दोहराते तो हर साल रहे हैं परन्तु धरातल पर यह कहीं लागू नहीं हो पा रही।

इस माह फिर से दोहराई गई इस घोषणा के आधार पर जब कुछ लोग इलाज कराने, सरकारी पैनल वाले अस्पतालों में गये तो उन्होंने कैशलेश से इन्कार करते हुए एडवांस पैसे की मांग की। मामला जब खट्टर तक पहुंचा तो बताया गया कि अभी तो केवल मत्स्य विभाग को ही इस प्रणाली में रखा गया है। वास्तव में यह सुविधा अभी तक किसी भी विभाग को नहीं मिल पा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने किसी भी निजी अस्पताल से इलाज के रेट बाबत कोई समझौता नहीं किया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने राज्य के तमाम सिविल सर्जनों को 17 नवम्बर को पत्र लिखे हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के निजी अस्पतालों को 'आयुष्मान' के रेट पर इलाज करने के लिये राजी करें। विदित है कि पहले से ही अनेकों अस्पताल आयुष्मान रेट छोड़कर पैनल से निकल चुके हैं। आयुष्मान रेट से कुछ बेहतर सीजीएचएस रेट माने जाते हैं। इन रेटों पर तो अस्पताल वाले कुछ हद तक राजी होने को तैयार हो सकते हैं, परन्तु हरियाणा सरकार यह रेट भी देने को तैयार नहीं है। इन हालात में समझा जा सकता है कि 'कैशलेश' का जो झुनझुना बीते चार-पांच सालों से बजता आ रहा है यूं ही बजता रहेगा।

अधिकारियों की हरामखोरी के चलते सालाना 275 करोड़ की बिजली चोरी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बिजली विभाग में अधिकारियों की रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हरियाणा सरकार ने वर्ष 1969 में विजिलेंस विभाग की स्थापना की थी। बीते करीब पांच साल पूर्व इसी विजिलेंस विभाग को बिजली चोरी रोकने व पकड़ने के लिये पुलिस थाने का स्वरूप भी दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही।

दरअसल बिजली विभाग का थाना स्वतः बिजली चोरी पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। वह तो केवल बिजली विभाग के अधिकारियों के बताने पर चोरों को पकड़ने व उनसे वसूली आदि कराने में मददगार ही हो सकता है, यानी जब तक विभागीय अधिकारी पहल न करे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब विभागीय अधिकारी हरामखोरी पर उतरे हों और चोरी पकड़ने में रुचि न रखते हों तो पुलिस भी क्या कर सकती है ?

इसका जीवंत एवं ताजातरीन उदाहरण इस संवाददाता को पिछले दिनों तब देखने को मिला जब उसने स्थानीय एसई को दिनांक 16 अक्तूबर को चोरी की सूचना देने के लिये उनके फोन नम्बर 9540954700 पर बात करनी चाही। जवाब में उन्होंने कहा कि लिख कर भेजो, बड़ा अजीब जवाब था, मानो कि संवाददाता उनसे कोई मेहरबानी मांग रहा हो। फिर भी संवाददाता ने उन्हें लिखित वॉटसएप संदेश भेजा। कोई कार्रवाई न देख कर 30 अक्तूबर को वही संदेश फिर दोहराया। कुछ न होता देख कर 2 नवंबर को पुनः एसई को फोन लगाया तो उनका जवाब था कि एमसीएफ वालों से कह कर उन झुग्गियों को हटवा दो। यानी कि चोरी तो बिजली विभाग की हो रही है और चोरों को हटवाने का काम यह संवाददाता करे।

एसई का यह उदासीन एवं लापरवाह व्यवहार देखने के बाद संवाददाता ने बिजली चोरी की अन्य सूचनाएं एसई को देने की जरूरत नहीं समझी। एसई से पहले यही सूचना सेक्टर 16 ए में बैठने वाले, इलाके के एसडीओ को भी दी गई थी। कुल मिलाकर तमाम विभागीय अधिकारियों को चोरी पकड़ने में कतई कोई रुचि नज़र नहीं आती। आए भी क्यों, उनके घर से क्या जा रहा है ? लाइन लॉस बढ़ता है बढ़े, इसका भुगतान तो उपभोक्ताओं से ही वसूला जायेगा। इसके विपरीत यदि यह वसूली इन अधिकारियों के वेतन से की जाए तो ये लोग फिर किसी सूचना देने वाले को यह नहीं कहेंगे कि लिख कर दो।

विज ने करनाल के एसपी को लगाया फोन..

इन्द्री। तंत्र-मंत्र कर चौगांवा गांव के युवक को चंद्राव में नहर में डूबोकर हत्या किए जाने के मामले में गृह मंत्री अनिल विज पीड़ित पक्ष की पीड़ा हरने का प्रयास में लग गए हैं। चौगांवा गांव के पीड़ित गृहमंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचे और सारे मामले की जानकारी देते हुए तांत्रिक पर तंत्र विद्या के जरिए युवक की हत्या करने के आरोप लगाए।

पीड़ित परिवार के अनुसार उनके बेटे को बीती रात कुछ लोगों ने जागरण के बहाने बुलाया था। आरोप लगाया कि तांत्रिक ने रात्रि को उनके बेटे को यमुना नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि बताए जाने के बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए था। घटना को अंजाम देने वाली आरोपी तांत्रिक पुलिस की लापरवाही के कारण फरार हो गया है। इस पर अनिल विज गम्भीर हो गए और करनाल के एसपी को फोन लगाकर तंत्र-मंत्र करने वाले हत्यारोपी पर तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विज ने एसपी को इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए।

करनाल नगर निगम और स्मार्ट सिटी लूट-भ्रष्टाचार का अड्डा बना : चौहान

करनाल। कांग्रेस सेवादल के प्रदेश महासचिव जोगिंदर चौहान ने खट्टर-मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश और देश मे भ्रष्टाचार के लिए भाजपा राजनेता तथा मंत्री जिम्मेदार हैं। भाजपा नेता, प्रदेश सरकार में मंत्री की शह पर बड़े अफसर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जब भी कोई अफसर फंसता है तो सभी नेता उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार को विपक्षी नेताओं में भ्रष्टाचार दिखाई देता हैं। जैसे ही वह नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो वह पाक साफ हो जाता है। सीबीआई व ईडी को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का लड़का और गृहमंत्री अमित शाह का पुत्र दिखाई नहीं देता हैं। जयंत शाह की पचास हजार रुपए की कंपनी पचास हजार करोड़ रुपए की कैसे हो गई इसकी जांच करने की हिम्मत न ईडी में है न सीबीआई में।

उन्होंने कहा कि करनाल में नगर निगम व स्मार्ट सिटी लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गई हैं। इसके लिए पार्षद और मेयर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सभी का कमीशन बंधा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हम कैसे ईमानदार कह सकते हैं जब उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार बढ़ रहा हैं। बिना मुख्यमंत्री की रजामंदी के उनके सीएमओ और अन्य अफसर किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। दावा किया कि पांचों राज्यों में भाजपा चुनाव हार रही हैं।

करनाल से भले मोदी जी ही खड़े हो जाएं, उन्हें भी हार का स्वाद चखना पड़ेगा। चौहान ने आरोप लगाया कि उन पर भी भाजपा में शामिल करने के लिए दबाव बनाया गया। इसके लिए उनके पेट्रोल पंप के आगे दीवार लगा दी गई लेकिन वह भाजपा के आगे झुकेंगे नहीं,संघर्ष करेंगे। भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ईडी और आयकर के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन हम कांग्रेसी झुकेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। प्रश्न के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाजपा में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है, कांग्रेस हरियाणा में उनके दम पर सरकार बनाएगी।